

कितनी है और अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ड) प्रत्येक मामले के लिए सरकार द्वारा अनुमति देने में कितना-कितना समय लगा?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बर एम् आर जनार्दनन): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उसने 138 मामलों में सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों से लोकसेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जो 30.06.1997 को मौजूद स्थिति के अनुसार, मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी हेतु लम्बित थे। उसके पश्चात्, 01 जुलाई, 1997 से 30 नवम्बर, 1998 के बीच की अवधि में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा लोक-सेवकों के संबंध में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने हेतु विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों को 330 मामले और भेजे गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त कुल 468 मामलों (138 + 330) में से 398 मामलों में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी गई है तथा ऐसे एक मामले में सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मामला मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने योग्य नहीं है। शेष रहे 69 मामले, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के सिलसिले में सक्षम प्राधिकारियों के पास आवश्यक जांच-पड़ताल और अपेक्षित कार्रवाई के विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। कुछ मामलों में आवश्यक जांच-पड़ताल और अपेक्षित कार्रवाई किए जाने में विलम्ब, उनके जटिल स्वरूप का होने, उनके संबंध में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग, विधि-कार्य-विभाग तथा संबंधित राज्य-सरकारों जैसे विभिन्न प्राधिकारियों से सलाह लिए जाने संबंधी अपेक्षा तथा न्यायालयों द्वारा दिए गए रोक-आदेशों के कारण हुआ है।

(ङ) मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान करने में लगा समय दर्शाने वाली तालिका संलग्न विवरण में है।

विवरण

398 मामलों में लोक-सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की अनुमति प्रदान करने में लगा समय

1. 1 महीने के भीतर	-	64
2. 3 महीने के भीतर	-	97
3. 6 महीने के भीतर	-	105
4. 6 महीने से अधिक	-	132
कुल	-	398

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में रिक्तियां

2136. प्रो रामगोपाल मादव:

श्री रमा शंकर कौशिक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय से संबंधित विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में रिक्त पदों को भरने के लिए सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बर एम् आर जनार्दनन): (क) और (ख) जी, हां। गृह-मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने, कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय की वर्ष, 1998-99 की अनुदान-मांगों के बारे में अपनी 44वीं रिपोर्ट में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में विशेषतः बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए, रिक्त पदों को भरे जाने की ज़रूरत दोहराई है।

(ग) 31.10.1998 को मौजूद स्थिति के अनुसार, रिक्त चल रहे 787 पदों में से 700 से अधिक पद भरने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पदों को भरने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में चल रही कार्रवाई में पदों का परिचालन आवेदन पत्रों का आर्पित किया जाना, चुने गये उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करवाया जाना तथा नियुक्ति-पत्रों का जारी किया जाना शामिल है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में रिक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया में संघ-लोक-सेवा-आयोग, कर्मचारी चयन-आयोग, राज्य-सरकारों, अन्य मंत्रालयों/संगठनों इत्यादि जैसे अधिकरणों से समन्वय तथा परामर्श किया जाना जुड़ा होता है। जुलाई 01, 1998 के पश्चात्, कुल 135 रिक्त पद भर लिए गए हैं। पुलिस-अधीक्षक तथा उससे ऊपर की रैंक के 14 अधिकारियों को उपर्युक्त ब्यूरो में लिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

Supreme Court Decision on Concessions to SC/ST Employees

2137. SHRI JIBON ROY:

SHRI C.O. POULOSE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state: